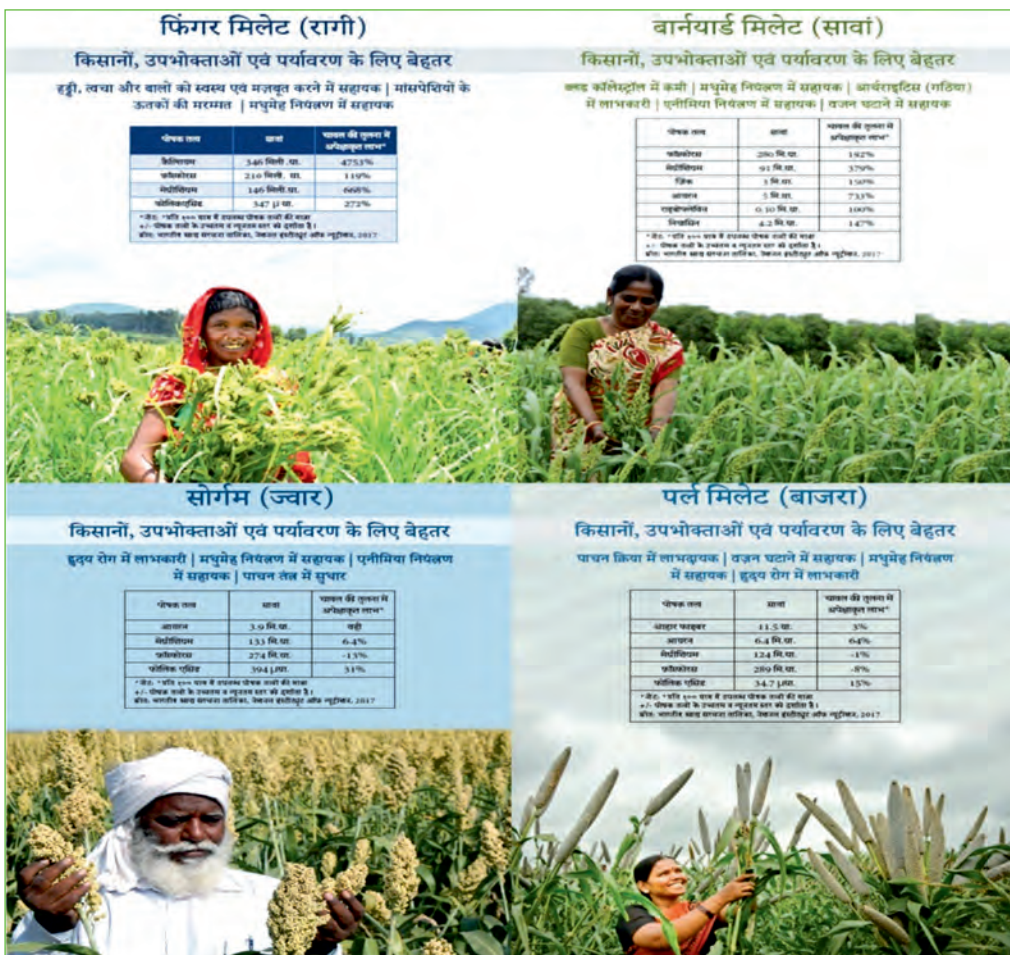




पौष्टिक अनाज हैं श्रीअन्न

नीलम पटेल*, शिवचरण मीणा** और सलोनी भूटानी***

श्रीअन्न (मिलेट्स), छोटे बीज वाली वार्षिक घासों का समूह है। ये मुख्य रूप से समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर अनाज फसलों के रूप में उगाए जाते हैं (एफएओ एवं इक्रीसेट वर्ष 1996)। देश में कई प्रकार के श्रीअन्न उगाए जाते हैं। ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चेना और सावां इत्यादि। ये अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ये फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और विटामिन 'ई' व 'बी' कॉम्प्लेक्स आदि के अच्छे स्रोत के रूप में भी जाने जाते हैं। श्रीअन्न विभिन्न व्याधियों जैसे कि रक्तस्राव विकारों, कृमि संक्रमण, पेट दर्द और पथरी को कम करने में भी मदद करते हैं। स्वास्थ्य लाभों के अलावा, श्रीअन्न पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनको कम पानी और लागत में सुगमता से उगाया जा सकता है।



वर्तमान में 130 से अधिक देशों में श्रीअन्न का उत्पादन किया जाता है। श्रीअन्न पूरे एशिया और अफ्रीका में 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए उनके पारंपरिक आहार का हिस्सा है। भारत में यह मुख्य रूप से एक खरीफ ऋतु की फसल है। इनमें अन्य फसलों की तुलना में सिंचाई, जल और कृषि आदानों की कम जरूरत होती है।

श्रीअन्न, आजीविका के अच्छे स्रोत

होने के साथ, किसानों की आय बढ़ाने और पूरे विश्व में खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अभूतपूर्व क्षमता रखते हैं। इनकी ये क्षमता, संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है एवं लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक भी है। श्रीअन्न या पौष्टिक अनाज के बारे में जागरूकता पैदा करने, उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के उद्देश्य से, संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न (मिलेट्स) वर्ष 2023 घोषित किया। इनके व्यापक उपयोग, अधिकतम उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न

हितधारकों के साथ विचार विमर्श व मंत्रणा की जा रही है।

इसी क्रम में, बजट भाषण वर्ष 2023-24 में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने श्रीअन्न को लोकप्रिय बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें 'श्रीअन्न', जिसका अर्थ है 'सभी अनाज की मां' या 'समृद्धि और अनाज' के रूप में संबोधित किया।

भारत में श्रीअन्न

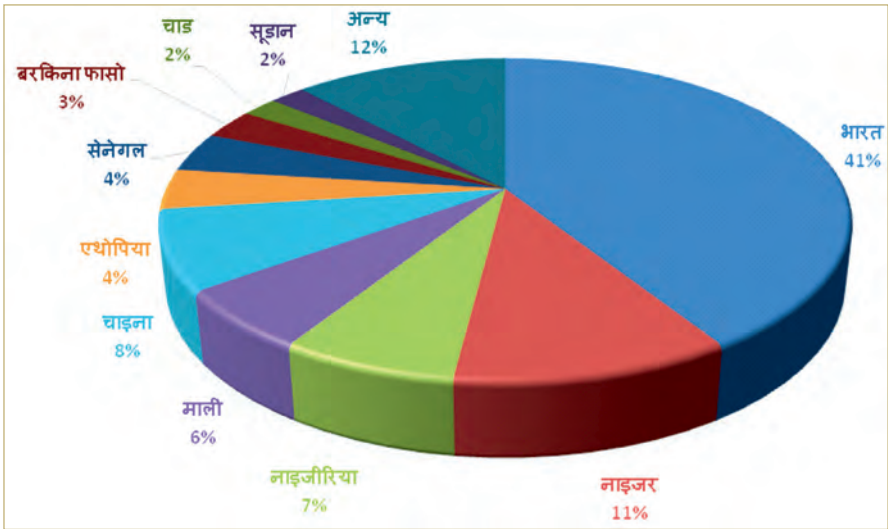
भारत, श्रीअन्न के उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ दुनिया का अग्रणी उत्पादक एवं दूसरा निर्यातक देश है।

*वरिष्ठ सलाहकार; **अनुसंधान अधिकारी; ***यंग प्रोफेशनल, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली

महत्वपूर्ण प्रयास

- श्रीअन्न के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 को राष्ट्रीय श्रीअन्न (मिलेट्स) वर्ष एवं श्रीअन्न को पोषक अनाज के रूप में नई पहचान दी गई।
- वर्ष 2018 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत श्रीअन्न (मिलेट्स) पर उपमिशन बनाया गया।
- कई राज्यों ने अपने स्तर पर श्रीअन्न मिशन शुरू किया।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण मिशन अभियान के तहत श्रीअन्न को शामिल किया गया।
- अब तक श्रीअन्न से संबंधित 200 स्टार्ट-अप को सहायता और 400 उद्यमियों (जिनका टर्नओवर 900 करोड़ रुपये से अधिक है) के लिए प्रौद्योगिकी सहायता दी गई।
- श्रीअन्न का निर्यात वर्ष 2017 से 2020 तक 24 मिलियन डॉलर से बढ़कर 26 मिलियन डॉलर हो गया।
- भाकृअनुप ने श्रीअन्न की 4 बायोफोर्टिफाइड किस्में एवं 13 उच्च उपज वाली किस्मों के साथ क्विनोआ (हिम शक्ति) नाम से एक उन्नत किस्म एवं कई मूल्यवर्धित प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं।
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम में श्रीअन्न को विशेष महत्व के तौर पर शामिल किया गया है।

देश में हरित क्रांति के समय वर्ष 1966-67 में 36 हजार हैक्टर क्षेत्र में श्रीअन्न उगाए जाते थे। अब वर्ष 2020-21 में यह क्षेत्र घटकर लगभग 14 हजार हैक्टर ही रह गया है। हालांकि, उत्पादकता के मामले में इसके उलट अभूतपूर्व वृद्धि देखने



विभिन्न देशों में श्रीअन्न के उत्पादन की हिस्सेदारी (स्रोत : एपीडा)

सारणी: श्रीअन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थिति (रुपये)

वर्ष	ज्वार	बाजरा	रागी
2017-18	1700	1425	1900
2018-19	2430	1950	2897
2019-20	2550	2000	3150
2020-21	2620	2150	3295
2021-22	2738	2250	3377
2022-23	2970	2350	3578
वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.74	8.69	11.13

(स्रोत : अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय)

को मिली है। यह वर्ष 1966-67 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 456 कि.ग्रा. से बढ़कर 1303 कि.ग्रा. तक पहुंच गई है।

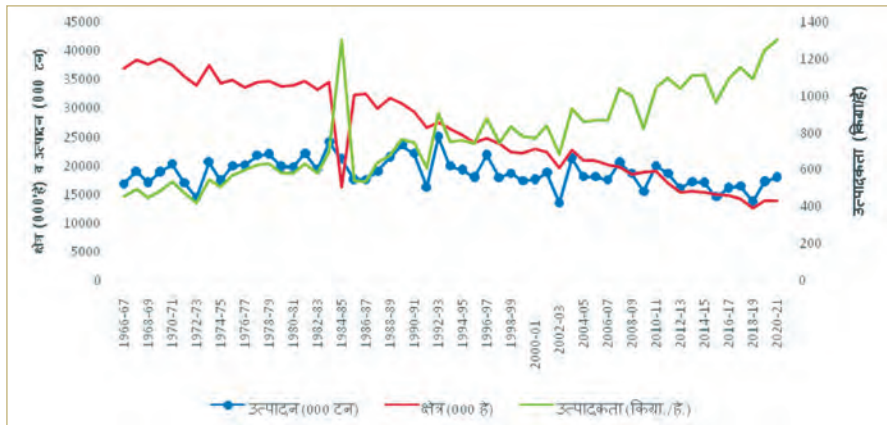
भारत में श्रीअन्न की खेती ज्यादातर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों में की जाती है। राजस्थान 39 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में श्रीअन्न का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत), हरियाणा (12 प्रतिशत), गुजरात (11 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9 प्रतिशत), महाराष्ट्र (5 प्रतिशत), कर्नाटक एवं तमिलनाडु

(2 प्रतिशत) आते हैं। देश में 60 प्रतिशत उत्पादन हिस्सेदारी के साथ बाजरा प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः ज्वार (27 प्रतिशत), रागी (11 प्रतिशत) एवं अन्य श्रीअन्न (2 प्रतिशत) उत्पादित किये जाते हैं।

धान और गेहूं, भारत में प्रमुख खाद्यान्न हैं, जो व्यापक रूप से उपलब्ध भी हैं। इससे श्रीअन्न के लिये बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए एवं श्रीअन्न की लोकप्रियता बढ़ाने तथा किसानों को इनके उचित मूल्य प्राप्ति हेतु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जा रही है। वर्ष दर वर्ष इसमें उचित वृद्धि भी देखने को मिल रही है। यह वृद्धि दर, रागी फसल के लिए पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक 11.13 प्रतिशत रही, जबकि ज्वार में यह वृद्धि 9.74 प्रतिशत एवं बाजरे के लिए 8.69 प्रतिशत पिछले पांच वर्षों में किसानों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

चुनौतियां

श्रीअन्न में आहार विविधता का विस्तार करने की विशाल क्षमता है। हालांकि, मांग और आपूर्ति के असंतुलन के चलते कालांतर

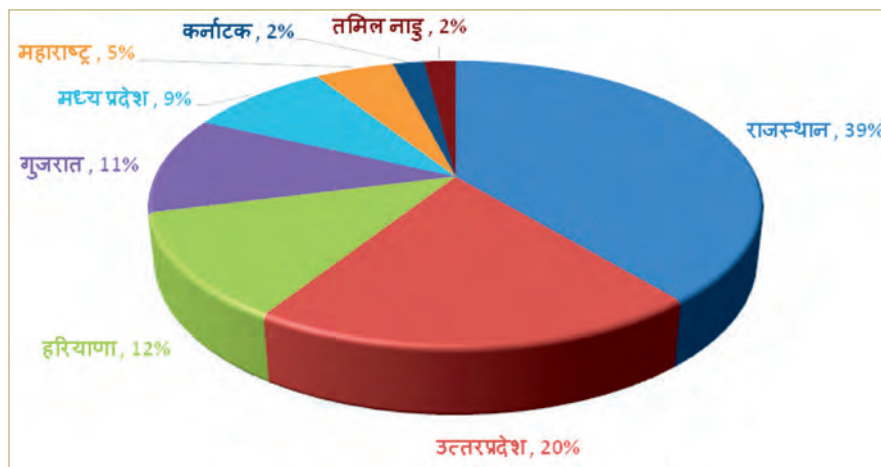


देश में श्रीअन्न का क्षेत्र (000 हैक्टर), उत्पादन (000 टन) एवं उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टर)

में इनके उत्पादन और उपभोग में कमी देखी गई। इनकी प्रतिव्यक्ति खपत में वर्ष 1962 से अब तक 32.9 कि.ग्रा. से 4.2 कि.ग्रा. तक कमी आई है। खपत में यह कमी समाज के निम्न आय वर्ग में सबसे अधिक पाई गई। ये अनाज सिर्फ उच्च वर्ग का आहार बनकर रह गए और गरीबों की थाली से दूर होते गए। इनकी खेती को प्रोत्साहन के लिए खरीद सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह आहार आदि में शामिल करने के संदर्भ में पर्याप्त नीतिगत सहयोग एवं समर्थन दिया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा ने इनके क्षेत्र विस्तार को गति प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित समस्याओं में भी कमी हुई है। विभिन्न संस्थानों और सरकारों द्वारा श्रीअन्न के प्रचार-प्रसार के कारण इनके महत्व के बारे में जागरूकता दिखाई देने लगी है। हालांकि श्रीअन्न की मांग एवं आपूर्ति को सतत बनाए रखने में कुछ प्रमुख द्विपक्षीय कारक हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

नीतिगत कदम

भारत सरकार, श्रीअन्न के प्रचार-प्रसार एवं इन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु कई नीतिगत प्रयास कर रही है। इनकी उत्पादन तकनीकों में विविधता लाकर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का निर्माण करना, स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम के तहत अन्य उद्यमी की तरह श्रीअन्न उद्यमी को प्रोत्साहन देकर इनको मुख्य धारा में लाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे



राज्यवार श्रीअन्न का उत्पादन वर्ष 2021-22 (स्रोत : एपीडा)

हैं। श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रचलित सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं एवं बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाने, अनुसंधान और विकास को मजबूत करने और संपूर्ण मूल्य शृंखला के विकास की दिशा में काम करने पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है।

भावी पथ

- श्रीअन्न के लिए बाजार व्यवस्था, एमएसपी की घोषणा, सार्वजनिक वितरण और स्कूल/आंगनबाड़ियों में श्रीअन्न का समावेश सुनिश्चित किया जाए। इनके अलावा एचएसएन कोड का निर्धारण, ग्रेड और मानकों का निर्धारण, निर्यात प्रोत्साहन आदि जैसे कुछ प्रमुख नीतिगत फैसलों से इनके उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- श्रीअन्न की सम्पूर्ण खाद्य शृंखला

के विकास हेतु विभिन्न हितधारकों जैसे-केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों, खाद्य वैज्ञानिकों, पोषण विशेषज्ञों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संघों (एफपीओ), स्टार्ट-अप आदि के बीच संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। नीति आयोग, एपीडा, एमएचआरडी, एमओएफपीआई, एमएसएमई आदि विभिन्न विभागों का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और भाकृअनुप के साथ तालमेल देश में श्रीअन्न को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

- श्रीअन्न को जलवायु अनुकूल और टिकाऊ कृषि के साथ एकीकृत कर, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शामिल करके उत्पादन में जोखिमों को कम किया जा सकता है।
- श्रीअन्न की खेती को प्राकृतिक खेती के साथ बढ़ावा दिया जा सकता है। देश की विभिन्न नदियों के दोनों ओर 5 से 10 कि.मी. क्षेत्र में इनकी खेती को फसल पद्धति में शामिल किया जा सकता है।
- वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली लगातार बढ़ती वैश्विक आबादी को खिलाने के लिए चुनौतियों का सामना कर रही है। श्रीअन्न एक किफायती और पौष्टिक विकल्प प्रदान कर इन चुनौतियों से पार पाने हेतु पूरे विश्व को सक्षम बना सकते हैं। अतः इनकी खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों की सलाहना करनी चाहिए। अन्य देश भारत के इस प्रयास से सीखकर इनकी खेती को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों के विरुद्ध स्वयं को सक्षम बना सकते हैं।

श्रीअन्न की मांग व आपूर्ति में कमी के कारण

मांग में कमी

- बढ़ता शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं की रुचि और बदलती प्राथमिकताओं से आहार की थाली भी बदल गई है।
- श्रीअन्न (विशेष रूप से ज्वार) के उत्पादों को तैयार करने के लिए परंपरागत ज्ञान की कमी एवं इसके पौष्टिक गुणों के बारे में उपभोक्ताओं में जानकारी का अभाव।
- इनके आटे को ज्यादा समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धान और गेहूं को श्रीअन्न की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है।

आपूर्ति में कमी

- मूल्यवर्धित श्रीअन्न उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं के बीच कम खपत, किसानों को इनकी खेती के प्रति हतोत्साहित करती है।
- कम उपज एवं अपेक्षाकृत कम लाभप्रद है।
- हरित क्रांति में धान और गेहूं को अधिक सहायता प्रदान की गई थी।
- गुणवत्तापूर्ण एवं उन्नत किस्म के बीजों का अभाव।
- सकल मूल्य शृंखला के लिए बुनियादी ढांचा जैसे-प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां, विशेष हलिंग-मिलिंग उपकरण आदि सुविधाओं की कमी।